पीलीभीत पुलिस

प्रेस नोट

जनपद पीलीभीत

वर्चुअल कान्फ्रेन्सिंग के जरिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद पीलीभीत में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारम्भ और उद्घाटन किया गया।

आज दिनांक 04.03.2025 को वर्चुअल कान्फ्रेन्सिंग के जरिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशान्त कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय के पर्यवेक्षण में जनपद पीलीभीत में क्रियान्वित **ई-ऑफिस का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया**। ई-ऑफिस पहल का उद्देश्य पुलिस विभाग में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। पीलीभीत के सभी शाखाओं में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया है। उद्घाटन के दौरान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार ने प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के प्रयासों की सराहना की। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा ई-ऑफिस के महत्व पर जोर दिया जो जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और पुलिस बल के समग्र कार्यप्रणाली को बढ़ाने में सहायक होगा। ई-ऑफिस एक digital workplace solution है। जिसका निर्माण NIC द्वारा किया गया है। ई-ऑफिस का विजन समस्त कार्यालय को सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कामकाज को प्राप्त करना है। यह केन्द्रीय सचिवालय नियमावली (CSMeOP) पर आधारित है ई-ऑफिस द्वारा कार्यालयो में की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही को कागजरहित तथा अत्यधिक तीव्र बनाये जाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

ई-ऑफिस के लाइव प्रजेंटेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा प्रधान कार्यालय में सुधार कार्य एवं अनुरक्षण हेतु 01पुलिस पेंशनर्स एवं अन्य 02 कर्मियों की मेडिकल क्लेम जिसकी राशि 02 लाख 41 हजार रुपये को ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया।

ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली:– पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा जनपद पीलीभीत में e-office प्रणाली की शुरुआत आज दिनांक 04.03.2025 में सर्वप्रथम पुलिस कार्यालय में की गयी। जिसके सफल क्रियावन के उपरान्त जनपद की समस्त शाखाओं में ई-आफिस प्रणाली शत-प्रतिशत लागू करने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे स्कैनर, लैपटॉप एवं अन्य उपकरण क्रय किये गये तथा जनपद में नियुक्त समस्त थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों की Gov ID व VPN तैयार कराया गया तथा समस्त प्रभारियों को ई-आफिस के माध्यम से हस्ताक्षर करने हेतु DSC (Digital Signature Certificate) बनवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही जनपद में ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु

एक नयी शाखा CRU का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समस्त प्रकार की प्राप्त डाक को डिजिटली पंजीकरण कर ई-आफिस के माध्यम से सम्पूर्ण जनपद को वितरित करेगा और जनपद पीलीभीत को डिजिटलाइज करने में अहम भूमिका निभायेगा। जनपद में ई-ऑफिस को पूर्ण रूप से लागू करने के लिये समस्त अधिकारी व कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रणाली के तहत आने वाले पत्राचार की स्कैनिंग और पंजीकरण के साथ-साथ पत्रावली बनाने, नोटिंग, रेफरेंसिंग, पत्राचार संलग्नकों, अनुमोदनार्थ आलेखों और अन्ततोगत्वा पत्रावलियों के साथ-साथ प्राप्तियों के संचरण समस्त कार्यवाही कागजरहित व इलेक्ट्रॉनिक ई-ऑफिस के माध्यम से की जायेगी। ई-ऑफिस प्रक्रिया से न सिर्फ दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी बल्कि कीमती समय की भी बचत होगी

मोटी-मोटी फाइलों का जमाना गुजरे जमाने की बात –उत्तर प्रदेश पुलिस में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाये गए हैं इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा **07 दिवस के अन्दर ई ऑफिस प्रणाली को सम्पूर्ण जनपद में समस्त थानों सहित शत प्रतिशत लागू किया जाना है** । पीलीभीत पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए शाखाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इस पहल के तहत थानों में मोटी-मोटी फाइलों का जमाना खत्म होगा और ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा।

ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को ई-ऑफिस की तकनीकी जानकारी दी गई है। ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिले में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सभी पुलिस थानों और कार्यालयों को आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य फाइलों और डेटा के डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। यह प्रणाली शिकायतों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेज बनाएगी, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही डिजिटल फाइल के जरिये मॉनिटरिंग से अधिकारियों को कार्यों पर नजर रखने और निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से जनता को भी कई लाभ होंगे। इससे थानों में लम्बित शिकायतों के निपटारे में देरी नहीं होगी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी के साथ समयबद्ध होगी।